



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2011/पौष 21, 1932

No. 111

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

विषय : यूरोपीय संघ (स्वीडन को छोड़कर) के मूल अथवा वहां से निर्यातित “पेंटाएरिथ्रिटॉल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत।

सं. 14/43/2010-डीजीएडी... मै. कनौरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ (स्वीडन को छोड़कर) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पेंटाएरिथ्रिटॉल” (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की “क्षति” तथा पाटन एवं “क्षति” के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतदद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की “क्षति” को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारम्भ करते हैं।

घरेलू उद्योग तथा उसका “मत”

3. यह आवेदन मै. कनौरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में अधिकांश हिस्सा मै. कनौरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. का है और वह समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है। इस प्रकार, यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की शर्तों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर मै. कनौरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. को “घरेलू उद्योग” माने जाने का प्रस्ताव है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद “पेंटाएरिथ्रिटॉल” (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है। पेंटाएरिथ्रिटॉल के एक कार्बनिक यौगिक होने का दावा किया गया है। “एरिथ्रिटॉल” नाम “पेंटाएरिथ्रिटॉल” से लिया गया है जो चार हाइड्रोक्साइड समूहों की उपस्थिति दर्शाता है और “पेंटा” उपसर्ग एक अणु में पाँच कार्बन परमाणुओं की मौजूदगी को दर्शाता है।

आवेदक के अनुसार पेंटाएरिथ्रिटॉल तकनीकी ग्रेड या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। दोनों ग्रेडों में प्रमुख अंतर कथित रूप से परिशुद्धता, क्रिस्टल के आकार और क्रिस्टलों की एकरूपता में होता है। कथित रूप से दोनों ग्रेडों का उत्पादन एक ही प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि यह श्रेणीकरण उत्पादन के पश्चात उत्पाद के विश्लेषणात्मक परीक्षण के चरण में ही संभव होता है। पेंटाएरिथ्रिटॉल की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक होती है और विस्फोटक सामग्री उद्योग में बेहतर क्रिस्टल संघटन का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए वाणिज्यिक शब्दावली में इस ग्रेड को “नाइट्रेशन ग्रेड” नामित किया गया है तथापि “नाइट्रेशन ग्रेड” के पेंटाएरिथ्रिटॉल का प्रयोग एल्काइड रेजिन्स अन्य उत्पादों (जहाँ दूसरे “तकनीकी ग्रेड” के पेंटाएरिथ्रिटॉल का प्रयोग किया जाता है) के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि कथित रूप से उत्पादन प्रक्रिया के कारण अधिकांशतः “तकनीकी ग्रेड” का उत्पादन होता है।

इस उत्पाद का उपयोग अधिकांशतः एल्काइड रेजिन्स, रेजिन इर्स्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, प्रिटिंग इंक, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक हेतु रस्टेबलाइजर, मॉडिफाइंग ड्राइंग ऑयकल्स, डेटोनेटर्स, विस्फोटक, भेषज, कोर ऑयल तथा कृत्रिम स्नेहकों के विनिर्माण में होता है। पेंटाएरिथ्रिटॉल सीमाशुल्क वर्गीकरण 29054200 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटन की जा रही संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के तहत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए।

अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

संबद्ध देश

6. वर्तमान याचिका यूरोपीय संघ (स्वीडन को छोड़कर) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में दायर की गई है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि ई यू के घरेलू बाजार में यह सामग्री जिस कीमत पर बेची जा रही है, उसका साक्ष्य जुटाने के हर संभव प्रयास किए गए थे तथापि आवेदक ई यू में वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत जो इस प्रयोजनार्थ सटीक एवं समुचित साक्ष्य हो सकती है, का कोई भी साक्ष्य जुटाने में असफल रहा है। अतः याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर उत्पादन लागत के अनुमानों पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। उसने यह अनुरोध किया है कि यह निर्धारित करने कि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा है या नहीं, के लिए उत्पादन लागतों के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना तर्कसंगत एवं पर्याप्त होगा। याचिकाकर्ता द्वारा मेथनॉल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, उद्योग के खपत संबंधी मानदंडों, भारत के अनुभव के आधार पर रूपांतरण लागत के अनुमानों, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा समुचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखा गया है। जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, यूरोपीय संघ (स्वीडन को छोड़कर) के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण की परिकलित पद्धति का सहारा लेकर सामान्य मूल्य के दावों को नियंत्रित किया गया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने आईबीआईएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा तथा पत्तन व्यय के आधार पर कीमत समायोजन की अनुमति दी गयी है।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के आधार पर आवेदक ने उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। यह पाया गया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित सिद्ध करता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयतों की संवर्धित मात्रा, कीमत कटौती, कीमत अवमूल्यन और लाभप्रदता, नियोजित पैंजी पर आय और घरेलू उद्योग हेतु नकद

प्रवाह में कमी के रूप में हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पाटनरोधी जाँच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाठित आयातों के परिणामस्वरूप आवेदक को हुई 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जाँच की अवधि

11. याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 09 - जून, 10 (15 माह) को जाँच की अवधि माने जाने का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति विश्लेषण के लिए अप्रैल, 06-मार्च, 07, अप्रैल, 07-मार्च, 08, अप्रैल, 08-मार्च, 09 और जाँच की अवधि को ध्यान में रखा गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में इस जाँच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस जाँच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

समय सीमा

13. इस जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसारण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना का गोपनीय और अगोपनीय सारांश (पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार) सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना की सार्थक समझ

प्रदान करने के लिए गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश में पर्याप्त व्यौरा शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित तथ्यों के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2011

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Pentaerythritol" originating in or Exported from European Union (excluding Sweden).

No. 14/43/2010-DGAD.— M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd. has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Pentaerythritol" (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union (excluding Sweden) (hereinafter also referred to as the subject country).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & 'Standing'

3. The Application has been filed by M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd. on behalf of the domestic industry. The production of M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd. accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article and is more than 50% of Indian production of the like article. The application thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Further, M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd. is proposed to be treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition is "Pentaerythritol" (also referred to as subject goods hereinafter). Pentaerythritol is claimed to be an organic compound. The name "erythritol" is claimed to have been derived from "Pentaerythritol" which indicates presence of four hydroxyl groups, and the prefix "Penta" indicates that there are five carbon atoms in the molecule.

The applicant has stated that Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is claimed to be in purity, crystal size and uniformity of crystals. Both the grades are claimed to be produced out of the same process. It has been submitted that gradation comes into picture only after production and at the stage of analytical testing of the product. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation is stated to be used in the explosive industry and therefore, this grade has been designated as "Nitration Grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as "Nitration Grade" can also be used for production of Alkyd Resins and other products (where the other grade "Technical Grade" Pentaerythritol is used). Production process, however, it is claimed, largely results in production of "Technical Grade".

The product is mostly used in the manufacture of Alkyd Resins, Resin Esters, Plasticizers, Printing inks, Synthetic rubber, Stabilizers for plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, and Core oils and Synthetic lubricants, etc. The product falls under customs classification 29054200. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of these investigations.

Like Articles

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules.

Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country for the purpose of the present investigation.

Subject Countries

6. The present petition has been filed in respect of alleged dumping of the product under consideration from European Union (excluding Sweden).

Normal value

7. The applicant has submitted that all possible efforts were made to get evidence of the price at which the material is being sold in the domestic market of EU. However, applicant has not been able to get any evidence of actual domestic selling price in EU which can constitute accurate and adequate evidence for the present purpose. Petitioner has therefore determined normal value based on estimates of cost of production based on international raw material prices. It has submitted that determination of normal value based on estimates of cost of production would be reasonable and sufficient basis to determine whether or not the product is being exported at significantly dumping prices. Petitioner has considered international price of methanol, consumption norms of the industry, estimates of conversion costs on the basis of Indian experience, selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. For the purposes of initiation, the normal value claims have been moderated by resorting to the constructed method of determination of normal value for exporters/producers from European Union (excluding Sweden).

Export Price

8. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from IBIS. Price adjustments have been allowed on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Inland Freight and Port expenses to arrive at the net ex-factory export price.

Dumping Margin

9. Based on the normal value and export price, the applicant has determined dumping margin for the product. It is found that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, *prima-facie*, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the ‘injury’ having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in profitability, return on capital employed and cash flow for the domestic industries. There is sufficient evidence of the ‘injury’ being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

11. The petitioner has proposed and taken April'09-June'10 (15 Months) as period of investigation. However, for analyzing injury Apr'06-Mar'07, Apr'07-Mar'08, Apr'08-Mar'09 and POI has been considered.

Submission of information

12. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.243, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.**

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority

9c-GI/11-3